(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) लोहा और इस्पात के मूल्यन और वितरण पर से दिनांक 16.1.1992 से नियंत्रण समाप्त किए जाने के पश्चात् इस्पात के प्रमुख उत्पादक अपनी आदान लागतों, सीमा शुल्क में हुए परिवर्तनों और विद्यमान बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने विभिन्न उत्पादों के मूल्य स्वंय निर्धारित कर रहे हैं। लोहा और इस्पात के गौण उत्पादक इस तारीख से पहले भी स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे।

सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जो यह सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे कि लोहा और इस्पात के उत्पादक उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपलब्ध हों। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:-

(i) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम हाथ में ले लिया गया है और निजी क्षेत्र में लोहा और इस्पात के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता के सृजन को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें, सुविधाएं दी जा रही हैं। लोहा और इस्पात के अनेक उत्पादकों द्वारा लोहा और इस्पात की और अधिक मात्रा की उपलब्धता से लोहा और इस्पात के मूल्यों पर संतुलित प्रभाव पड़ने का अनुमान है।

(ii)लोहा और इस्पात उद्योग हेतु कच्चे माल के आयात पर और पूंजीगत माल के आयात पर भी सीमा शुल्क में कमी करने से लोहा और इस्पात उत्पादकों को उत्पादन में कमी करने में सहायता मिलेगी।

(iii) लोहा और इस्पात के आयात के खुली अनुमति हैं। लोहा और इस्पात उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क में कमी करने से ऐसे आयातों की उतराई लागत कम हो गई है।

Wrong assessment of annual turnover ot drugs

513. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have wrongly assessed the annual turnover of drugs;

(b) the rate of per Kg. of each drug based on which the annual turnover was worked out;

(c) whether the prices of medicines based on olybenelamide, diazepam, diphenoxylate, hydarocholoride and increased around 2 to 300 per cent and the value has been taken based on the price of the bulk drugs under 1987 DPCO;

(d) the prices of medicines based on these drugs under DPCO 1987 and their present prices; and

(e) whether the bulk drug turnover has not been worked out based on the price increase of the medicines and steps taken to rework the prices on actual basis?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) to (e) Bulk Drug turnover data as collected and compiled by the Expert Group of the Standing Committee appointed to review the Drug Policy, 1986 has been utilised in the exercise of identification of drugs for price control.

अतिरिक्त भूमि पर कब्जा

514. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या ग्रामीण और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि सीमा नियतन के पश्चात् देश में पुरानी रियासतों के पास असीमित अतिरिक्त भूमि पड़ी हुई है और इससे कई निर्धन किसानों को यह भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है,

(ख) यदि हां, तो ऐसी रजवाड़ी भूमि का अनुमानित कुल क्षेत्र कितना है,

(ग) इसमें से कितनी भूमि विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमों से संबद्ध है,

(घ) क्या सरकार ने इन विवादों को जल्दी निपटाने के लिए कोई कार्रवाई की है, और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) से (ग) इस प्रकार का कोई मामला केन्द्रीय सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) और (ड़) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट खनन

515. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में समेकित ग्रेनाइट खनन परियोजनायें स्थापित करने का विचार रखती है,

(ख) यदि हां, तो अब तक मूल रूप से कितनी परियोजनाओं की योजना तैयार की गई है,

(ग) मध्य प्रदेश में अब तक कितनी ग्रेनाइट परियोजनायें शुरू की गई हैं, और

(घ) इन परियोजनओं में निवेश की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) : (क) मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट खनन परियोजनाएं स्थापित करने के बारे में केन्द्र सरकार की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) ग्रेनाइट के गौण खनिज होने के कारण, इस बारे में खनिज रियायतें देने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा केन्द्र सरकार ऐसी परियोजनाओं के बारे में सूचनाएं समेकित नहीं करती।

Subsidy on Fertilizers

516. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are giving subsidy on different kinds of fertilizers;

(b) if so, the quantum of subsidy being given variety-wise;

(c) whether some of the Southern States have made a demand to enhance the subsidy component on the fertilizers;

(d) if so, the response of Government in this regard;

(e) whether Government have made a study of the impact of fertilizer prices on the agricultural output; and

(f) rf so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN): (a) Yes, Sir.

(b) During 1994-95, Rs. 3622.35 crores were spent on account of retention price subsidy which included certain payments in respect of phosphatic fertilizers for period prior to decontrol and Rs. 1166 crores on account of imported urea. In addition, Rs. 514.02 crores were paid under the scheme of sale of decontrolled phosphatic and potassic fertilisers.

(c) Yes, Sir.

(d) No decision in this regard has been taken.

(e) No, sir.

(f) Does not arise.

Production of Fertilizers

517. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the production of fertilizers in the country during the last three years, year-wise with breaking of productions under private and public sector units respectively;

(b) the quantity of fertilizer imported in the last three years, year-wise and the corresponding expenditure on this account both in US dollar and rupee terms;